POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2024/अंक 07

मासिक प्रेषण दि. 8 जुलाई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 जुलाई, 2024 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! इस बार लोकसभा चुनाव परिणाम पिछले दो चुनाव जैसे नहीं रहे। इस बार कोई भी राजनीतिक दल अकेले दम पर सरकार बनाने में विफल रहा है। ऐसा लगा, मानो मतदाताओं ने साबित किया हो कि वह विकल्प खड़ा कर सकने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए विपक्ष की भूमिका भी मजबूत है।

प्रसन्नता है, ऐसे हालातों के बीच नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस बार वह अपने सहयोगी दलों के सहारे पर हैं। मद्देनजर, बड़ी सूझबूझ के साथ सभी समीकरणों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार सर्वपंथ समभाव व सर्वमत से चलेगी। यह राष्ट्र की प्रगति के लिए एक साथ मिलकर चलने का वक्त है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।

माना जा रहा है कि सर्वमत की बात के जरिए मोदी ने अपने सहयोगियों और देश के नागरिकों को आश्वस्त किया है कि फैसले सभी को भरोसे में लेकर होंगे। यह सामने भी आया, शपथ ग्रहण में सहयोगी घटक दलों की मौजूदगी में मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व के प्रति किसी तरह की नाराजगी नहीं रही। भरोसा भी दिया... हम साथ हैं और साथ रहेंगे। मोदी ने स्पष्ट कहा भी है कि अब राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर न केवल सरकार को बल्कि पूरे देश को एक साथ चलना है। देश की प्रगति के लिए सरकार में बड़े और कड़े फैसले होकर रहेंगे।

राजनीतिक विश्लेषक इस बार के चुनावों को लेकर अपने अलग-अलग विचार व्यक्त कर रहे हैं। मेरा मानना है, चुनाव परिणामों ने देश की राजनीतिक दशा और दिशा को एक नया मोड़ दिया है। नई सरकार के लिए यह लाजमी हो गया है कि वह जनता के विश्वास पर खरी उतरे। इसके लिए सरकारी तंत्र की कार्यशैली में सुधार लाना बेहद जरूरी है। क्योंकि, इसी से सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेहिता जुड़ी है।

मोदी सरकार का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प तभी साकार हो सकेगा जब खेती-किसानी, बेरोजगारी, औद्योगिक विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी अनेक चुनौतियों से निपटने में प्रशासन चुस्त और दुरुस्त होगा।

वकील उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे से बाहर-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि वकीलों पर सेवा में 'खामी' के लिए उपभोक्ता अदालत में केस नहीं चलाया जा सकता। वकील उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने एक अपील पर यह फैसला सुनाया, जिसमें सवाल उठाया था कि क्या सेवाओं में कमी के लिए वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

फैसले में कहा कि वकीलों की सेवा अलग तरह की है। उपभोक्ता संरक्षण कानून से उन्हें बाहर रखना चाहिए। उक्त फैसले में शीर्ष कोर्ट ने कंज्यूमर कमीशन का 2007 का वह फैसला रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उपभोक्ता अधिकारों का ध्यान रखते हुए अगर वकील ठीक से सेवा नहीं देते हैं तो उन्हें उपभोक्ता अदालत में लाया जा सकता है। पीठ ने फैसले में यह भी कहा कि फीस देकर कोई काम करवाने को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की 'सेवा' के दायरे में नहीं रखा जा सकता। अगर वकील गड़बड़ी करते हैं तो उनके खिलाफ सामान्य अदालतों में मुकदमा चलाया जा सकता है।

दिव्यांग को डिफेक्टिव डी-फ्रीज बेचना पड़ा भारी

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय में किशनगढ़ निवासी दिव्यांग ओम प्रकाश कुमावत ने परिवाद दायर कर बताया कि पूरी तरह दिव्यांग होने पर राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसे जीविकोपार्जन के लिए किशनगढ़-रेनवाल बस स्टैंड लाखेरा पर सरस डेयरी बूथ आवंटित किया था। डेयरी बूथ में दूध, दही, पनीर व अन्य खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उसने डी-फ्रीज खरीदा था, लेकिन वह डिफेक्टिव निकला। मामले की खुद पैरवी करते हुए उसने आयोग को सारी जानकारी दी।

सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने ओम प्रकाश कुमावत के पक्ष मे फैसला देते हुए डिफेक्टिव डी-फ्रीज बेचने को अनुचित व्यापार प्रथा करार दिया। आयोग ने विपक्षी पार्टियों (डी-फ्रीज विक्रेता और निर्माता कंपनी) पर 2.15 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं विपक्षियों को निर्देश दिया है कि वे डी-फ्रीज की कीमत 29,500 रुपए भी परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित ओम प्रकाश कुमावत को दें।

किसानों को मिलेंगे 'जौ' के नये बीज

जयपुर स्थित राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर दुर्गापुरा अब गेहूं की तरह बिना छिलके वाली 'जौ' की किस्म तैयार कर रहा है। राजस्थान में बढ़ते जल संकट के बीच कम पानी और खारे पानी में भी इसकी खेती आसानी से हो सकेगी। इसके अलावा यह देश के मैदानी इलाकों में भी पैदा हो सकेगा।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा की इस खोज पर अब केंद्र और राज्य सरकार के साथ-साथ देशभर में कई विश्वविद्यालय इसकी उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। बीज तैयार होने पर करीब 600 क्विंटल बीज प्रदेश के किसानों को दिया जाएगा। जौ में बीटा ग्लूकन नामक रेशा होता है जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। इससे इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। अगले कुछ वर्षों में जौ प्रमुख खाद्यान्न के रूप में न केवल भारत में बल्कि विश्व में एक अलग पहचान बना लेगा।

सबसे ज्यादा डार्क जोन राजस्थान में

देश के 6533 ब्लॉकों में से 27 फीसदी में भूगर्भ जल काफी नीचे खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 की जारी रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से अति शोषित क्षेत्र हैं। हालांकि यहां रिचार्ज के लिए जल उपलब्ध है।

दूसरी ओर, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से देश के अत्यधिक जल शोषण क्षेत्र में हैं। यहां

सीमित मात्रा में वाटर रिचार्ज का विकल्प है। देश के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश और रिचार्ज की पहल करने से भूजल की स्थिति में सुधार हुआ है। देश में भूगर्भ जल की सबसे खराब हालत राजस्थान में है। यहां सबसे ज्यादा 203 क्षेत्र डार्क जोन में है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इस संकट से निपटने के लिए उच्च स्तर पर जल संग्रहण के उपाय अति आवश्यक हैं।

किसान निधि की 17वीं किस्त जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद अपने पहले निर्णय में किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किए। इससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा और करीब 20 हजार करोड़ रुपए बांटे जाएंगे।

फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद मोदी ने कहा, 'हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध सरकार है। इसलिए यह उचित है कि कार्यभार संभालते ही जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए जाएं वह किसान कल्याण से संबंधित हो। हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करते रहना चाहते हैं।

गरीबों के लिए बनेंगे 3 करोड़ घर

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए तीन करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह निर्णय आम चुनाव के बाद बनी नई केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया है।

गौरतलब है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। इसके तहत अब तक 4.21 करोड़ आवास निर्मित हो चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को घर निर्मित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत बने आवासों में बिजली, पानी, शौचालय तथा एलपीजी जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाती है।

राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी

देश में युवा सबसे ज्यादा रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से वित्त वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही के लिए जारी सर्वे के मुताबिक देश में सभी आयुवर्ग के लोगों की बेरोजगारी दर जहां 6.7 फीसदी रही, वहीं 15 से 29 साल के बीच के युवाओं में बेरोजगारी दर 17 प्रतिशत रही। यानी नौकरी और रोजगार की तलाश कर रहे हर 100 में से 17 युवाओं को काम नहीं मिला।

सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक युवाओं (लड़के-लड़कियों) की सबसे कम बेरोजगारी वाले टॉप राज्यों में मध्यप्रदेश, तो सबसे अधिक बेरोजगारी वाले शीर्ष 5 राज्यों में राजस्थान शामिल है। राजस्थान के युवाओं की बेरोजगारी दर 24 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि हर 100 में से 24 युवा काम की तलाश में हैं, पर उन्हें नौकरी या रोजगार नहीं मिल रहा।

'नीम के गांव' के नाम से प्रसिद्ध गांव

प्रदेश के अजमेर जिले का पदमपुरा गांव एक ऐसा गांव है जहां गांव की आबादी से करीब ढाई गुना ज्यादा नीम के पेड़ लगे हैं। इन नीम के पेड़ों पर न तो कभी कुल्हाड़ी चली न ही काटकर नुकसान पहुंचाया गया। पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है।

यह गांव 'नीम के गांव' के नाम से प्रसिद्ध है। नीम के पेड़ों की वजह से शहर व आस-पास के गांवों से यहां का तापमान काफी कम रहता है। नीम का सबसे बड़ा फायदा कोरोना के समय दिखा। गांव में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं था। गांव में करीब 350 घर है, सभी घरों के बाहर नीम के घने पेड़ लगे हैं।

गर्मी में नीम के पेड़ों के नीचे लोग आराम करते मिलेंगे। वे कहते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे उन्हें अलग ही गंध महसूस होती है। अन्य गांवों के लोग व जनप्रतिनिधि भी गांव की परंपरा से प्रेरित होकर आगे आने लगे हैं और वे भी नीम के पौधे लगाकर सघन हरियाली बढ़ाएंगे।

गांवों में बनेंगे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी एक बड़ी समस्या है। मौसम विभाग ने अच्छे मानसून की भविष्यवाणी करके एक खुशखबर दी है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 में प्रदेश के 20 हजार गांव-ढाणियों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, ताकि जल संरक्षण के कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके।

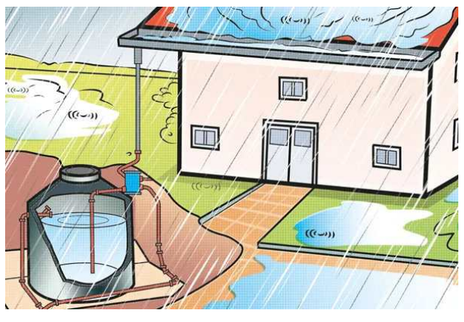

ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में आमजन को समुचित जल उपलब्ध कराने की दिशा में यह अभियान संजीवनी साबित होगा। उन्होंने कहा कि योजना की सफलता के लिए जन साधारण की भागीदारी आवश्यक है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि सभी कार्य निर्धारित समय में पूरा हो।

प्रौद्योगिकी को बनाएं रचनात्मक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीर देशों से कहा, प्रौद्योगिकी को रचनात्मक बनाएं, विनाशकारी नहीं। तभी हम समावेशी समाज की नींव रख पाएंगे। हमें मिलकर आने वाले समय को हरित युग बनाने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम तनावों और अनिश्चितताओं के दौर से उबर पांएगे।

उन्होंने इटली के अपुलिया में हो रहे जी-7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह नसीहत दी। आज ग्लोबल साउथ के देश दुनिया भर में इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। मोदी ने भारत में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर ठोस उपाय करने होंगे। सम्मेलन में जी-7 के सभी सदस्य देशों ने इस दशक में जीवाश्म ईंधन की कटौती पर तेजी से काम करने को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई।

महिला किसान ने किए खेती में नवाचार

प्रदेश में सीकर जिले के गांव बेरी की किसान संतोष देवी खेदड़ को जैविक खेती में किए गए नवचारों को लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। संतोष 16 वर्षों से जैविक खेती कर रही है। वह स्वयं अपने बगीचे की नर्सरी में जैविक विधि से दर्जनों किस्म की पौध तैयार करती है।

उन्हें जैविक खेती में किए नवाचारों व उपलब्धियों पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया। संतोष 10वीं कक्षा तक पढ़ी है और अपने बगीचे में नर्सरी व बागवानी रिसर्च सेंटर भी चला रही है। अब तक वह हजारों किसानों को जैविक खेती व बागवानी के नए-नए गुर सिखा चुकी है।

प्रदेश में लगाए जाएंगे 7 करोड़ पौधे

पर्यावरण संरक्षण को नई गति देने के लिए प्रदेश में 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान' शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सात करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 3 करोड़ पौधे आमजन को रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

इनमें से 3 करोड़ पौधे राजकीय भूमि और एक करोड़ पौधे ओरण एवं चरागाह भूमि पर लगाए जाने हैं। पेड़ पौधों की भूमिका पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अमूमन हरियाली बढ़ाने के नाम पर खानापूर्ति सामने आती रही है। राजस्थान में गर्मी के प्रकोप का कारण भी यही है। गांवों से लेकर शहरों तक अवैध कटाई से हरियाली चौपट हो गई है। जहां भी पौधारोपण हो वहां पौधों की सार-संभाल आवश्यक है, नहीं तो अकसर बहुत से पौधे पेड़ बनने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं।

शिक्षक भर्ती में बढ़ेगा महिला आरक्षण

प्रदेश सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का फैसला किया है। प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 2.70 लाख से अधिक पद है। इनमें करीब 60 हजार पद खाली है। इन पर भर्ती होती है तो करीब 30 हजार पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके साथ ही राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। संशोधन के बाद 50 फीसदी आरक्षण लागू होगा। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार का फोकस महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर ज्यादा है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर